

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2022

G.C.M.S. No. 2022/112

दर्ज दिनांक : 05.05.2022

अपीलार्थी:

1. उम्मेदसिंह पुत्र नींबसिंह, उम्र 65 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बांगड़ी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. जबरसिंह पुत्र नींबसिंह के का.मु.-
1/1 हनवंतसिंह पुत्र जब्बरसिंह
1/2 जितेन्द्रसिंह पुत्र जब्बरसिंह
1/3 दिनेशसिंह पुत्र जब्बरसिंह
1/4 हंसराज कंवर पुत्री जब्बरसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र नींबसिंह
3. करणसिंह पुत्र नींबसिंह
4. स्व. देवीसिंह पुत्र नींबसिंह के का.मु.-
4/1 लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह
4/2 दुर्गेशसिंह पुत्र देवीसिंह
4/3 विजयलक्ष्मी पुत्री देवीसिंह
4/4 विलमकंवर पत्नि देवीसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम बांगड़ी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
5. राजस्थान सरकार/भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2015 बअनवान जब्बरसिंह बनाम करणसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

पैरोकार-

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पॉडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2015 बअनवान जब्बरसिंह बनाम करणसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में मौजा ग्राम बागड़ी पटवार हल्का खिमाडा, तहसील

सुमेरपुर के हाल खसरा नम्बर 375, 376, 377, 378, 379 व 387 कुल खसरा 06 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

0.57 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जो अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 4 की सयुक्त खातेदारी की थीं। परन्तु रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के विरुद्ध दौराने राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में आपस पस में सांठ-गांठ कर एक वाद घोषणार्थ/बंटवाडा/स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त भूमिया आपसी सहमति बंटवाडा अनुसार खातेदार करणसिंह देवीसिंह, उम्मेदसिंह पिसरान् नीबसिंहजी ने राजेन्द्रसिंह, जबरसिंह पिसरान् नीबसिंहजी के पक्ष में कर दी है, जिससे उक्त खातेदारी में हमारे (रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2) नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज की जाये। इसके लिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ ही पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रपत्र पेश किया जाता है और न्यायालय के सामने भ्रामक एवं कूटरचित दस्तावेज पेश कर राजस्व कर्मचारियों के मिली भगत करते हुए बाले बाले एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए अधिनस्थ न्यायालय से रेकॉर्ड से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई हैं। अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये एवं सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे इसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को कभी कोई जानकारी नहीं रही है। हाल ही में आज से करीब 20 दिन पूर्व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी को खसरा नम्बर 375 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल से अपने हिस्से पर काबिज रहते उसे कब्जा खाली करने हेतु कहा और कहा कि उक्त भूमि सम्पूर्ण रूप से राजस्व रेकॉर्ड में हमारे नाम दर्ज है इसलिये इसके मालिक हम है। तब अपीलार्थी ने सम्बन्धित राजस्व रेकॉर्ड की ऑनलाईन जाच की एवं बाद जांच यह जानकारी में आया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 ने भ्रामक व कुटरचित दस्तावेज तैयार करवा कर अपने पक्ष में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगती कर एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए जैस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। जिस जानकारी के बाद अपीलार्थी द्वारा जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जिसका रेकॉर्ड कार्यालय में जमा नहीं होना जाहिर किया गया तब अपीलार्थी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कहने पर पटवारी हल्का द्वारा हाल ही में उक्त वाद-पत्र एवं सम्बन्धित कार्यवाही दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये गये, जिसके बाद अपीलार्थी को नकले दिनांक 28.04.2022 को प्राप्त हुई, जिसको देखने पर उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की

जाकर रेस्पोंडेण्ट्स व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत कैम्प कोर्ट खिमाडा में वादीगण राजेन्द्रसिंह, जब्बरसिंह पि. नींबसिंह द्वारा प्रतिवादीगण करणसिंह, देवीसिंह, उम्मेदसिंह पि. नींबसिंह के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र राजीनामा प्रपत्र में दिनांक 29.05.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संलग्न बंटवाड़ा प्रस्ताव पर हम सहमत है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में ही दिनांक 29.05.2015 को अपीलाधीन डिक्री पारित की गई। जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन के साथ दिनांक 05.05.2022 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये एवं सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे इसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को कभी कोई जानकारी नहीं रही है। हाल ही में आज से करीब 20 दिन पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी को खसरा नम्बर 375 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल से अपने हिस्से पर काबिज रहते उसे कब्जा खाली करने हेतु कहा और कहा कि उक्त भूमि सम्पूर्ण रूप से राजस्व रेकॉर्ड में हमारे नाम दर्ज है इसलिये इसके मालिक हम है। तब अपीलार्थी ने सम्बन्धित राजस्व रेकॉर्ड की ऑनलाईन जांच की एवं बाद जांच यह जानकारी में आया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगाय 3 ने भ्रामक व कुटुरचित दस्तावेज तैयार करवा कर अपने पक्ष में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगती कर एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए जैस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। जिस जानकारी के बाद अपीलार्थी द्वारा जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जिसका रेकॉर्ड कार्यालय में जमा नहीं होना जाहिर किया गया तब अपीलार्थी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कहने पर पटवारी हल्का द्वारा हाल ही में उक्त वाद-पत्र एवं सम्बन्धित कार्यवाही दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये गये, जिसके बाद अपीलार्थी को नकले दिनांक 28.04.2022 को प्राप्त हुई, जिसको देखने पर उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावे।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.05.2015 को प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र में बतौर प्रतिवादी अपीलांट के हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर अपीलांट द्वारा अपीलमीमो पर किए गए हस्ताक्षर से प्रथमदृष्टया समान

है। अतः अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि अपीलांट को अपीलाधीन डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद माफिक राजीनामा प्रकरण आपसी सहमति से बंटवाड़ें के लिए तहसीलदार सुमेरपुर को राजीनामा प्रपत्र एवं आपसी पारिवारिक सहमति पत्र के साथ तहसीलदार को अग्रेषित किया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन डिक्री की बखूबी जानकारी थी। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए प्रस्तुत कारण विश्वसनीय, युक्तियुक्त व समुचित नहीं हैं। साथ ही चूंकि अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the

aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory



subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरणों



में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 2555 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 2555 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।



आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्थान अपील प्राधिकारी, पाली
पाली